(ङ) क्या यह सच है कि पेट्रोल, डीजल और एल॰पी॰जी॰ विक्रय केन्द्र मात्रा और दूरी के आधार पर खोले जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालु): (क) और (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार पेट्रोल/डीजल की खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप, तेल उद्योग द्वारा अनुपालन किए जा रहे मात्रा दूरी मानकों को पूरा करने वाले स्थानों पर खोले जाते हैं। इसी प्रकार एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिप 10,000 और अधिक की जनसंख्या वाले कैस्बों में चरणबद्ध ढंग से खोलने की योजना बनाई जाती है बशर्ते कि 15 कि॰मी॰ के अर्धव्यास के भीतर पड़ने वाले निकटवर्ती गावों सहित उक्त कस्बे की संभाव्यता, व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चलाए रखने के लिए पर्याप्त हो। डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को खोलने में आवश्यक आधारभूत सिद्धान्त उक्त क्षेत्र में प्रचातनरत मौजूदा डीलरों/डिस्ट्रब्यूटरों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित किए बिना उत्पादों की आसान उपलब्धता के लिए कार्यतंत्र का विस्तार करना है।

(ख) सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें नीचे दी गई हैं:-

	राष्ट्रीयता	- भारतीय
	आयु	- अनु॰ जाति/ज॰जा॰/शारीरिक रूप से विकलांगों, रक्षा और सामान्य श्रेणियों के लिए 21—50 वर्ष - उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 35 वर्ष और अधिक। - स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
	शैक्षणिक योग्यताएं	
(1)	अनु॰ जाति/जनजाति, शारीरिक विकलांग रक्षा और सामान्य श्रेणी	- मैट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष
(2)	स्वतंत्रता सेनानी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी	- लागू नहीं
	आय	
	व्यक्ति	- 50,000/- रूपये प्रतिवर्ष
	सहकारी समितियां	- कोई सीमा नहीं।
	निवास	
(1)	अनु॰ जाति/जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक विकलांगों के लिए	- संबंधित जिले को वरीयता देते हुए विज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार निकटवर्ती जिलों के निवासी।
(2)	स्वतंत्रता सेनानी और सामान्य श्रेणियां	- संबंधित जिले के निवासी।
(3)	रक्षा, उत्कृष्ट खिलाड़ी और शारीरिक विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांगों के अलावा अन्य	- संबंधित राज्य के किसी भी जिले के निवासी।

(IREDA) and Canara Bank. Under the scheme, IREDA provides soft loans for industrial and institutional systems directly (at interest rates of 8.3% to industries and 5% to non-profit making organisations respectively) and for domestic systems through its financial intermediaries (at a maximum rate of 5% to end users). Canara Bank provides soft loans for domestic users and small establishments at an interest rate of 5.5%. The Canara Bank scheme is at present operational in Bangalore, Mangalore, Mysore, Delhi, Madras and Pune only. Further, a rebate of 0.5% on the above interest rates is available for installation of BIS (Bureau of Indian Standards) approved solar collectors. The interest subsidy scheme is also applicable to solar driers, solar stills for water purification etc. through IREDA.

(c) Solar water heating is a well established technology in many parts of the world. In some countries, there are even mandatory provisions for using solar water heaters in residential buildings. In India also, the technology is considered to be reasonably well established. The economic viability of domestic solar water heaters which usually replace use of electricity is well recognised. From the national point of view, savings in conventional fuels and significant reduction in peak load demands of electricity with wider use of solar water heaters, result in substantial savings in investments required for additional generating capacity. Environmental benefits are added advantages.

Construction of roads in Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan

159. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RUVL AREAS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of the centrally sponsored schemes for construction of roads in Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan during the last three years;

(b) the central funds allocated to those States in each year during this period;

(c) the annual outlay for the schemes for these States during 1995-96 and 1996-97; and

(d) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) to (d) This Ministry is not implementating any scheme for construction of roads in Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. However, one Centrally Sponsored Sheme, viz: 'Roads in Special Problem Areas of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan' is being implemented for construction of roads in specific areas, i.e. dacoity infested areas of these three States. Central funds available during each year are allotted to these States in the ratio of 48% to Uttar Pradesh, and 26% each to Madhya Pradesh and Rajasthan. The annual outlay to these States during 1994-95 to 1996-97 is given in the Statement. (See below) The implementation of this Centrally Sponsored Scheme is monitored by the Government.

Statement

National outlay to states during last three years for construction of roads

State	1994-95 Outlay/ Allocation	1995-96 Outlay/ Allocation	1996-97 Outlay/ Allocation
Uttar Pradesh	0.96	0.96	0.96
Madhya Pradesh	0.52	0.52	0.52
Rajasthan	0.52	0.52	0.52
TOTAL:	2.00	2.00	2.00

पैट्रोल पंप/एल॰पी॰जी॰ एजेन्सियों हेतु मानदंड

160. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्रों और एल॰पी॰जी॰ एजेन्सियां खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आबंटितियों के संबंध में पात्रता शर्तों और अन्य मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन श्रेणियों और व्यक्तियों के लिए विशेष विवेकाधीन कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में ऐसे कितने केन्द्र खोले गए हैं; और